

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 122/2022

गुगन आयु 85 वर्ष पुत्र जोरा, जाति जाट, निवासी गिडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

आवेदक

बनाम

1. उमराव आयु 55 वर्ष पुत्र हनुमान, जाति जाट, निवासी गिडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनू।
3. उपखण्ड अधिकारी चिडावा जिला झुंझुनू।

— अनावेदक

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राज0 टी0 एक्ट बाबत स्थानान्तरण प्रकरण उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टी0 एक्ट मु0नं0 14/2013 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिडावा तारीख पेशी 13.04.2022

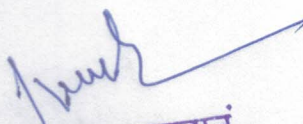
उपस्थित:-

1. श्री शिवनारायण सिंह, अभिभाषक — आवेदक की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरिया, अभिभाषक — अनावेदक संख्या 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — अनावेदक संख्या 2 व 3 की ओर से।

आदेश


दिनांक 08.06.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रार्थी व अन्य की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 436 तादादी 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 437 तादादी 0.85 हैक्टर वाके ग्राम गिडानिया में से अपना अपनी खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 478 तादादी 0.06 हैक्टर में से ग्राम गिडानिया की तरफ आवागमन करने हेतु हमेशा से रास्ता स्थित होना बतलाते हुये अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी नं0 1 ने अदालत मातहत के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से साठ-गांठ कर कानून के विरुद्ध प्रार्थी व अन्य की जमीन व्यथित होकर प्रार्थी व अन्य की ओर से न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी स्वीकार केम्प कोर्ट झुंझुनू में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 06.11.2018 को खारीज किये जाने पर प्रार्थी की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 03.06.2020 को प्रार्थी व अन्य की निगरानी स्वीकार कर अदालत मातहत व


जिला कलक्टर झुंझुनू

अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को खारीज करते हुये पुनः उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवाई जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय करने का आदेश दिया। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की बिना किसी प्रकार से पालना करते हुये उभय पक्षकारान् की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर बिना पत्रावली के रिकॉर्ड पर लिये ही तारीख पेशी दिनांक 25.03.2022 को अप्रार्थीगण नम्बर 6/1 लगायत 6/4 की तामील बिना किसी अधिकार के मानते हुये बार-बार आवाज दिलवाई जाना बतलाते हुये इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश दिया तथा पत्रावली आयन्दा मौका रिपोर्ट बहस हेतु दिनांक 01.04.2022 दी। दिनांक 01.04.2022 को प्रार्थी/अप्रार्थी नं० 1 की ओर से उक्त सभी अनियमितताओं को अदालत मातहत को अवगत करवाया इसके बावजूद अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने बहस हेतु अंतिम अवसर देते हुये तारीख पेशी 08.04.2022 दी। दिनांक 01.04.2022 को ही अप्रार्थी नं० 1 ने प्रार्थी व अन्य को धमकी दी कि उसने अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर सौदा तय कर लिया है तथा फैसला प्रार्थी के विरुद्ध करवा कर ही रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के वर्तमान पीठासीन अधिकारी, महोदय धारा 251ए राज० टी० एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये समस्त प्रार्थना पत्रों में हर सप्ताह तारीख पेशी देकर पक्षकारान पर ले देकर फैसला करवाने का दबाव बनाते है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय ने अप्रार्थी नं० 1 से अपना सौदा तय कर प्रकरण का निर्णय प्रार्थी के खिलाफ देने का पक्का मानस बना लिया। इस पर तारीख पेशी दिनांक 08.04.2022 को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह आंशका प्रकट की गई की प्रार्थी को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है तथा प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य किसी सक्षम अदालत में स्थानान्तरित किये जाने के लिए कार्यवाही करने हेतु एक माह की अवधि का समय दिये जाने का निवेदन किया परन्तु अदालत ने अपने लालचवश प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2022 की बिना प्रवाह किये अप्रार्थी नं० 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र ले लिया तथा बिना बहस सुने ही आदेशिका में बहस सुनी जाना लिखा जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.04.2022 दी। अदालत मातहत के उक्त कन्डक्ट से यह साफ जाहिर है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी विपक्षी नं० 1 से मिले हुये है तथा प्रकरण का निर्णय प्रार्थी के विरुद्ध करने पर आमदा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र तुरन्त दर्ज किया जाकर अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाकर इस पत्रावली को अन्य किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ० धारा 251ए राज० टीनेन्सी एक्ट मु० न० 14/2013 की पत्रावली तुरन्त तलब की जाकर बाद सुनवाई उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रांक 350 दिनांक 26.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि


जिला कलेक्टर झुन्झुनू

प्रा० पत्र की बिन्दू सं० 1 में वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है शेष प्रश्न में प्रार्थी के वकील द्वारा न्यायालय में गलत व्यवहार करना व अपनी सभी पत्रावली में किसी प्रकार की बहस नहीं करना व जबाब नहीं देना लेकिन न्यायालय में तो पत्रावली में आगामी कार्यवाही करनी होती है अन्यथा अप्रार्थीगण को न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाता और प्रकरण में कार्यवाही लम्बित रहती है जो प्रार्थी कार्यवाही को लम्बित करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पिछली 2-3 पेशियों से पत्रावली स्थानान्तरण हेतु कहते रहे लेकिन प्रार्थी के वकील द्वारा न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि पत्रावली स्थानान्तरण की जावे या प्रकरण की कार्यवाही को रोक दी जावे। प्रार्थी द्वारा न्यायालय पर लगाये गये आरोप गलत है। शेष प्रश्न में प्रार्थी को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है। बिन्दू सं० 2 व 3 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नहीं है। आवेदक उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय में करवाना चाहता तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अपने लालचवश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2022 की बिना परवाह किये अप्रार्थी नं० 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र ले लिया तथा बिना बहस सुने ही आदेशिका में बहस सुनी जाना लिखा जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.04.2022 दी। अदालत मातहत के उक्त कन्डक्ट से यह साफ जाहिर है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी विपक्षी नं० 1 से मिले हुये हैं तथा प्रकरण का निर्णय प्रार्थी के विरुद्ध करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ० धारा 251ए राज० टीनेन्सी एक्ट मु०न० 14/2013 की पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

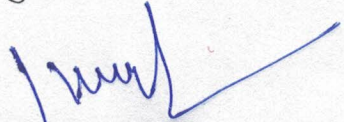
वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा में विचाराधीन उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ० धारा 251ए राज० टीनेन्सी एक्ट मु०न० 14/2013 की पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर कोई आपत्ति नहीं की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।


जिला कलेक्टर झुंझुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुआ भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 14/2013 उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी चिडावा मुकदमा संख्या 14/2013 उनवानी उमराव बनाम गुगन वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में दिनांक 07.07.2022 को उपस्थित हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिल्हा करमदार झुंझुनूं